भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 407

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

.....

एनएमसीजी की प्रगति

407. श्री जावेद अली खान;

श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2014 से आज की तिथि तक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के तहत गंगा नदी की सफाई के लिए लगभग 14,000/- करोड़ रुपये खर्च किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी गंगा का पानी पीने योग्य या नहाने योग्य नहीं होने के क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) और (ख): गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को फिर से जीवंत करने के लिए 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम जून 2014 में शुरू किया गया था। कार्यक्रम को बाद में 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया था। वित्तीय वर्ष (एफवाई) 2014-15 से 31 दिसंबर 2022 तक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) को कुल 13,709.72 करोड़ रुपये जारी किए गए थे, जिसमें से 13,245.68 करोड़ रुपये एनएमसीजी द्वारा राज्य सरकारों, स्वच्छ गंगा राज्य मिशनों और अन्य एजेंसियों को गंगा संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वितरित किए गए हैं। 2014-15 से 31 दिसंबर, 2022 तक परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य के साथ संकलित राज्य और एजेंसी-वार परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एनएमसीजी द्वारा विभिन्न एजेंसियों को वितरित राशि अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

(ग): नदी संरक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) द्वारा अधिसूचित खुले में स्नान के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता

मानदंडों को पूरा करना है न कि पेयजल की गुणवत्ता को। सतही जल को, जिसमें नदियों का जल भी शामिल है; पीने योग्य या मानव उपभोग के लिए उपयुक्त बनाने के लिए आवश्यक उपचार/शुद्धिकरण से गुजारा जाना अपेक्षित है।

नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) के माध्यम से 5 मुख्य धारा वाले राज्यों में 97 स्थानों पर गंगा नदी के जल की गुणवत्ता का आकलन कर रहा है। 2022 (जनवरी से अक्टूबर) के लिए सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, गंगा नदी की देखी गई जल गुणवत्ता इंगित करती है कि घुलित ऑक्सीजन (डीओ), जो नदी के स्वास्थ्य का एक संकेतक है, को अधिसूचित प्राथमिक स्नान जल गुणवत्ता मानदंड की स्वीकार्य सीमा के भीतर पाया गया है और यह गंगा नदी के लगभग पूरे विस्तार के लिए नदी के पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने की दृष्टि से यह संतोषजनक है। बहु क्षेत्रीय उपायों के परिणामस्वरूप, वर्ष 2014 और 2022 (जनवरी से अक्टूबर) के जल गुणवत्ता मानकों के मध्यमान डेटा अर्थात डीओ, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) और फीकल कोलीफॉर्म (एफसी) की तुलना के अनुसार; 33 स्थानों पर क्रमशः डीओ (मध्यिका); 41 स्थानों पर बीओडी और 28 स्थानों पर एफसी में सुधार हुआ है ।

गंगा नदी की सफाई एक सतत प्रक्रिया है और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण और रिजुवनेशन के लिए विभिन्न परियोजनाओं को लागू कर रहा है।

*****

अनुलग्नक-1

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

2014-15 से 2022-23 के दौरान एजेंसी-वार जारी की गई धनराशि और अन्य बेसिन वाइड व्यय का विवरण

(करोड़ रुपए में)

राज्य	**लाभार्थी एजेंसियां**	**उद्देश्य / लक्ष्य**	**कुल**
उत्तराखंड	स्वच्छ गंगा के लिए राज्य मिशन (एसएमसीजी)	*सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड आउटरीच एक्टिविटीज*	801.98
	वाप्कोस लिमिटेड	*घाट और श्मशान घाट परियोजनाएं*	86.45
	राज्य वन विभाग	*वनीकरण*	110.20
	हाइब्रिड वार्षिकी मोड (एचएएम) परियोजनाएं	*सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स*	86.82
	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	*प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण*	1.20
	स्वच्छता मिशन	*ग्रामीण स्वच्छता योजना*	30.69
	कुल योग		1,117.34
उत्तर प्रदेश	स्वच्छ गंगा के लिए राज्य मिशन (एसएमसीजी)	*सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड आउटरीच एक्टिविटीज*	2,428.23
	राज्य सरकार-सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर	*सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स*	70.00

	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	*घाट और श्मशान घाट परियोजनाएं*	302.50
	राज्य वन विभाग	*वनीकरण*	113.62
	अन्य- जाजमऊ टेनरी एफ्लुएंट ट्रीटमैंट एसोसिएशन (जेटीईटीए)	*औद्योगिक प्रदूषण उपशमन*	178.77
	हाइब्रिड वार्षिकी मोड (एचएएम) परियोजनाएं	*सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स*	813.61
	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	*प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण*	14.81
	स्वच्छता मिशन	*ग्रामीण स्वच्छता योजना*	408.35
	कुल योग		4,329.89
बिहार	स्वच्छ गंगा के लिए राज्य मिशन (एसएमसीजी)	*सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड आउटरीच एक्टिविटीज*	3,028.60
	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	*घाट और श्मशान घाट परियोजनाएं*	73.55
	राज्य वन विभाग	*वनीकरण*	76.48
	हाइब्रिड वार्षिकी मोड (एचएएम) परियोजनाएं	*सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स*	88.73
	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	*प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण*	2.31
	स्वच्छता मिशन	*ग्रामीण स्वच्छता योजना*	256.76
	कुल योग		3,526.43
झारखंड	स्वच्छ गंगा के लिए राज्य मिशन (एसएमसीजी)	*सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड आउटरीच एक्टिविटीज*	164.52

	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	*घाट और श्मशान घाट परियोजनाएं*	30.52
	राज्य वन विभाग	*वनीकरण*	22.74
	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	*प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण*	4.44
	स्वच्छता मिशन	*ग्रामीण स्वच्छता योजना*	27.83
	कुल योग		250.05
पश्चिम बंगाल	स्वच्छ गंगा के लिए राज्य मिशन (एसएमसीजी)	*सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड आउटरीच एक्टिविटीज*	881.17
	राज्य वन विभाग	*वनीकरण*	23.55
	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड-घाट और श्मशान परियोजनाएँ	*घाट और श्मशान घाट परियोजनाएं*	20.04
	हाइब्रिड वार्षिकी मोड (एचएएम) परियोजनाएं	*सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स*	177.17
	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	*प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण*	1.19
	स्वच्छता मिशन	*ग्रामीण स्वच्छता योजना*	236.00
	कुल योग		1,339.12
मध्य प्रदेश	पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, जबलपुर	*सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स*	9.89
दिल्ली	दिल्ली जल बोर्ड	*सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स*	1,253.86
हरियाणा	सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग	*सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स*	89.61
राजस्थान	अर्बन इम्प्रूवमेंट	*सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स*	71.25

	ट्रस्ट कोटा		
हिमाचल प्रदेश	सिंचाई विभाग	*सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स*	3.75
बेसिन वाइड	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)	*जल गुणवत्ता और औद्योगिक प्रदूषण निगरानी के लिए सहायता*	147.83
	एनएमसीजी और अन्य एजेंसियां	*निष्पादन एजेंसियों, अनुसंधान और पायलट परियोजनाओं, अर्थ गंगा परियोजनाओं, आउटरीच और संचार परियोजनाओं और हस्तक्षेपों, कार्यालय प्रशासनिक व्यय, परियोजना समर्थन परामर्श आदि के माध्यम से परियोजना हस्तक्षेप।*	1,106.66
सकल योग			13,245.68

*****